



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2483

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44620 वर्ष 2025

रामभवन

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : मानवेन्द्र सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., राजकुमार वर्मा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से दाखिल प्रतिशपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री मानवेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री राजकुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से तथा श्री दीपक कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 264 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 324(4) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता, थाना बिंदकी, जिला फतेहपुर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। आवेदक से मोबाइल, बेल्ट, अपराध में प्रयुक्त हथियार, चश्मा एवं मोटरसाइकिल के पुर्जों की झूठी बरामदगी दिखाई गई है। उक्त बरामदगी विभिन्न स्थानों से, जो कि खुले स्थान हैं और सबके लिए सुलभ हैं, की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि शव के अवशेष पहले ही आवेदक पर थोपी गई उक्त बरामदगी से प्राप्त हो चुके थे। आवेदक को केवल इसलिए अभियुक्त बनाया गया है क्योंकि मृतक के साथ आवेदक की पत्नी सरिता के अवैध संबंध थे। आवेदक की पत्नी सरिता को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 41788 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का मामला उक्त सह-अभियुक्त सरिता के समान है। आवेदक को आरोपित आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 11.7.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि शव के अवशेषों का डीएनए प्रोफाइल उसके परिवार के सदस्यों से मेल खाता है, जिससे यह पुष्ट होता है कि शव उल्लिखित मृतक का ही था।
8. विद्वान अधिवक्ता सूचनाकर्ता की ओर से ने भी इस आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया है कि मृतक की मोटरसाइकिल एवं अन्य सामग्री की बरामदगी आवेदक के इशारे पर हुई है, अतः वह जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।
9. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को नियम तथा कारावास को अपवाद की संकल्पना को जन्म देता है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार केवल इस कारण छीना नहीं जा सकता कि उस पर अपराध करने का अभियोग है, जब तक कि उसका अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उद्घोषित करता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायोचित एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया है।



11. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के वाद में पुनः इस बात पर बल दिया है कि इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को नहीं भूला जाना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बता सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।
13. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध कोई सुसंगत साक्ष्य नहीं है तथा सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
14. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **रामभवन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।